संख्या-11/2016/345/एक-4-16-16बी-4/15 टी0सी0

प्रेषक,

बीरबल सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0 प्र0,लखनऊ।
2- मण्डलायुक्त, सहारनपुर ।

राजस्व अनुभाग-4 **लखनऊ दिनांक 31 मार्च, 2016**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में जिला प्रशासन के अन्तर्गत आयुक्त हेतु निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहन क्रय किये जाने की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में अपर आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, के निष्प्रयोज्य (अम्बेसडर कार) संख्या यू0पी0-11ई-0001, के प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहन के रूप में 01 बोलेरो वाहन क्रय किये जाने हेतु धनराशि रू0 6,64,102 (रू0 छः लाख चौंसठ हजार एक सौ दो मात्र) की स्वीकृति अनुदान संख्या-50, लेखा शीर्षक-2053-जिला प्रशासन-आयोजनेत्तर-101-आयुक्त-03- मुख्य कार्यालय-14-मोटर गाड़ियों का क्रय मद में किये जाने तथा उक्त हेतु तदनुसार पूर्णांकित रू0- 6.65 लाख की धनराशि 2053-जिला प्रशासन-आयोजनेत्तर-101-आयुक्त-03- मुख्य कार्यालय-01 वेतन मद में होने वाली बचतों से पुनर्वनियोंग के माध्यम से स्वीकृत/व्यय किये जाने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त व्यय वित्तीय नियम संग्रह के सुसंगत क्रय नियमों एवं मितव्ययिता सम्बंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अनुसार समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए वाहन का क्रय स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत ही किया जायेगा। वाहन के क्रय के पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि जिस निष्प्रयोज्य वाहन के स्थान पर नये वाहन का क्रय किया जा रहा है , उसके सापेक्ष पूर्व में वाहन का क्रय नहीं किया गया है। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि निष्प्रयोज्य हुए वाहन के सापेक्ष शासन अथवा अन्य स्रोत से पूर्व में किसी प्रकार की धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है।

(2) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत निष्प्रयोज्य वाहन अनुदान संख्या -50 के अर्न्तगत जिला प्रशासन के लिए वाहनों की मद से ही क्रय किया गया हो। धनराशि का उपयोग केवल वाहन के क्रय के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 में ही किया जायेगा तथा वाहन का क्रय निर्धारित प्रक्रिया एवं सुसंगत क्रय नियमों/वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सूक्ष्म तथा लघु उद्योग विभाग व राजस्व विभाग में निर्धारित नीति के अनुसार बोलेरो वाहन का क्रय डी0जी0एस0 एण्ड डी0 रेट पर किया जायेगा, वाहन क्रय करने के पश्चात धनराशि अवशेष बचती है तो उसे कोषागार में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहनों का क्रय किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलाम किये गये वाहन सरकारी वाहन ही थे एवं उक्त निष्प्रयोज्य वाहन मण्डलायुक्त को ही आवंटित थे तथा वाहन प्रतिस्थापन में द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(4) शासन द्वारा जिस प्रकार के वाहन के क्रय की अनुमति या स्वीकृति प्रदान की गई है, उसी प्रकार के वाहन को क्रय करके शासन को एक माह के अन्दर उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। तत्पश्चात ही संबंधित जनपद को अन्य वाहन स्वीकृत किये जाने पर विचार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-50, लेखाशीर्षक-2053-101-आयुक्त-03-मुख्य कार्यालय-14-मोटर गाडियों का क्रय मद के अन्तर्गत संलग्नक-1 (बी0एम0-9) में उल्लिखित मानक मदों के सम्मुख हो रही बचतो से पुनर्विनियोग के माध्यम से वहन किया जायेगा।

3- स्वीकृत धनराशि से संबंधित बजट जनपदों को आनलाइन करने की कार्यवाही राजस्व परिषद द्वारा तत्काल सुनिश्चित की जायेगी ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या-ई-5-810(1)/दस-2016 दिनांक 31 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त। (बी0एम0-9)

भवदीय,

(बीरबल सिंह)
उप सचिव ।

संख्या-11/2016/345(1)एक-4-16-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1- महालेखाकार लेखा एवं हकदारी (प्रथम),उ0प्र0, इलाहाबाद/ (लेखा परीक्षा)प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ ।
3- कोषाधिकारी सहारनपुर ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-5
5- वित्त (आय व्ययक)अनुभाग-2।
6- राजस्व अनुभाग-6
7- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(बीरबल सिंह)
उप सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।